राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 244/2022

कमलेश पुत्र शंकर लाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी बालमुकुंदपुरा उर्फ बासड़ा, पुलिस थाना कोठकावाड़ा, जयपुर (दक्षिण)

----**अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य-पी.पी. के माध्यम से

----**प्रत्यर्थी**

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	सुश्री अनुभा सिंह
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री राजेंद्र यादव, एएजी
		श्री शेर सिंह महला, पीपी के साथ
		श्री विजय सिंह शेखावत

माननीय न्यायमूर्ति फरजंद अली

निर्णय

आदेश सुरक्षित करने की तिथि	:	11.01.2022
आदेश उच्चारित करने की तिथि	:	27.02.2023

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>न्यायालय द्वारा:-</u>

1. वर्तमान अपील सीआरपीसी की धारा 374(2) के तहत दायर की गई है जो सत्र वाद संख्या 28/2021 में विद्वान विशेष न्यायामूर्ति, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, संख्या 03, जयपुर महानगर-I द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश दिनांक 05.10.2021 के खिलाफ है जिसके तहत अपीलार्थी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 (ड)/6 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2,00,000/- रुपये के जुर्माने

की सजा सुनाई गई, जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. संक्षेप में, एफआईआर के अनुसार मामले के तथ्य यह हैं कि नौ वर्ष की एक लड़की 26.09.2021 को शाम करीब 5 बजे अपने दादा के लिए गांव की एक दुकान से बीड़ी लेने के लिए घर से निकली थी। जब लड़की बीड़ी और मिठाई लेकर लौट रही थी, तो आरोपी-अपीलार्थी ने उसे फुसलाया, उसे एक गुप्त स्थान पर ले गया और उसके साथ बलात्कार का अपराध किया। उसने उसके हाथ और मुंह बांध दिए थे और उसका गला घोंटने की भी कोशिश की थी। यह सोचने के बाद कि वह मर गई है, आरोपी-अपीलार्थी घटनास्थल से चला गया। जब लड़की काफी देर तक वापस नहीं आई तो ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की और उन्हें बेहोश पड़ा पाया। वह बदहवास हालत में थी और उसके निजी अंगों से खून बह रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसने अपने पिता को पूरी कहानी बताई। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने पर जांच शुरू हुई।

3. अपनी सामान्य जांच के हिस्से के रूप में, पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए, अपराध स्थल का निरीक्षण किया, साइट योजना तैयार की, पीड़िता की उम्र से संबंधित दस्तावेज हासिल किए, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया और उसकी चिकित्सकीय जांच की गई। पीड़िता का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया, आरोपी-अपीलार्थी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। एक पूछताछ नोट तैयार किया गया और पूछताछ के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 एबी और पोस्को अधिनियम, 2012 की धारा 5/6 के तहत अपराध सिद्ध हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसके द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार, अपराध स्थल का सत्यापित नक्शा पूरी जांच करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद पुलिस ने 27.09.2021 को याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 कख और पोस्को अधिनियम, 2012 की धारा 5/6 के तहत अपराध के लिए आरोप-पत्र दायर किया।

4. इसके बाद, दिनांक 28.09.2021 के आदेश के तहत, ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया

और आरोपी-अपीलार्थी के खिलाफ पोस्को अधिनियम की धारा 5 (ड)/6 और आईपीसी की वैकल्पिक धारा 376कख के तहत अपराध के लिए आरोप तय किए गए।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा कम से कम 16 गवाहों की जांच की गई और 33 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, जब आरोपी-अपलार्थी से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई, तो उसने अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की गवाही का खंडन किया और दावा किया कि अभियोक्ता पीडब्लू-14 की गवाही के उस हिस्से को छोड़कर सभी गवाह झूठे थे, जिसमें उसने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि वह नशे में था। आरोपी के बचाव में उसके पक्ष में चार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

6. इसके बाद, आरोपी और सरकारी अधिवक्ता के अधिवक्ता को सुनने और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की जांच करने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आरोपी-प्रत्यर्थी को पोस्को अधिनियम की धारा 5 (ड)/6 के तहत दोषी ठहराया और उसे पीड़ित होने की सजा सुनाई। बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 2,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया। दोषसिद्धि के उक्त निर्णय और सजा के आदेश से व्यथित होकर आरोपी-अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है क्योंकि मामले के सही तथ्यात्मक और विधिक पहलुओं से निपटा नहीं गया है। आरोपी जल्दबाजी में की गई जांच का शिकार है। एजेंसी ने एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर जांच पूरी कर इस मामले में आरोप-पत्र दायर किया। अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में बाधा उत्पन्न हुई क्योंकि जब उसे पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान नहीं की गई थी। अधिवक्ता द्वारा ***खत्री एवं अन्य बनाम बिहार सरकार और अन्य*** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर अवलंब जताया गया।

8. आगे यह भी कहा गया कि पूरा मुकदमा छह दिनों के भीतर समाप्त हो गया और जांच एजेंसी और ट्रायल कोर्ट की जल्दबाजी के कारण अरोपी के साथ अन्याय हुआ। 28.09.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को उसी दिन न्यायालय में बुलाया गया, आरोप-पत्र दिया गया और बिना तैयारी के समय के

आरोप तय करने के बिंदु पर बहस करनी पड़ी। मामले की प्रतिदिन सुनवाई का अनुरोध करने वाले अभियोजन पक्ष के आवेदन पर उत्तर दायर करने के लिए उक्त अधिवक्ता को समय नहीं दिया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ट्रायल कोर्ट अभियोजन के प्रति पक्षपाती था और न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया।

9. उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में विसंगतियां हैं। एफएसएल को भेजे गए आरोपी के नमूनों से संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और इससे नमूने भेजने और परिणाम प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा होता है। हालांकि, अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपी नशे में था और मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए आरोपी के बयान से भी यही बात सामने आ रही है, फिर भी इस तथ्य की पुष्टि के लिए एजेंसी द्वारा कोई परीक्षण नहीं किया गया। जांच की पूरी प्रक्रिया, आरोप-पत्र दायर करना, मुकदमा चलाना और आरोपी के अपराध पर अंतिम राय देना कानून के अनुरूप नहीं है और इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने की आवश्यकता है।

10. आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए, इस न्यायालय ने अभियोजन के मामले का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ पीड़ित के हितों को बचाने के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता को बुलाना उचित समझा। इसके बाद, वह उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया कि मामला संवेदनशील था और इसका निर्णय केवल इस कारण से किया गया कि पीड़ित को बिना किसी अनुचित देरी के न्याय दिया जाए। ट्रायल कोर्ट ने सोचा-समझा, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन किया और फिर कानून के अनुसार निर्णय सुनाया, इस प्रकार, वर्तमान मामले में हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं है।

11. विद्वान एएजी ने सरकारी अभियोजक के साथ मिलकर अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई जल्दबाजी ने आरोपी के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया क्योंकि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य उस पर मामला दर्ज का कथित अपराध और उसे सलाखों के पीछे डालने के लिए पर्याप्त थे।

12. इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान ट्रायल जज ने तथ्यों पर उचित विचार-विमर्श के बाद निर्णय पारित किया था और यह कानून के

अनुसार है। अभियुक्त ने पीड़िता के खिलाफ जघन्य अपराध किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों ने अभियोजन पक्ष के मामले को किसी भी उचित संदेह से परे सिद्ध कर दिया, इस प्रकार, उन्होंने प्रार्थना की कि अपील खारिज कर दी जाए और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जाए।

13. उन्होंने आगे कहा कि यह एक नाबालिग से बलात्कार का गंभीर मामला है और निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय एक तर्कसंगत निर्णय है, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. पक्षों के अधिवक्ता सुने गए। आक्षेपित निर्णय की सावधानीपूर्वक जांच करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद और इस विशेष मामले में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया और तरीके के बारे में अपनी टिप्पणियां शुरू करने से पहले, यह न्यायालय वर्तमान प्रकृति वाले मामले को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों और दिशानिर्देशों पर चर्चा करना चाहेगा।

15. किसी बच्ची से बलात्कार से जुड़े मामलों को सावधानीपूर्वक और कुछ हद तक संवेदनशीलता के साथ निपटाने की आवश्यकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ***मोहम्मद आलम बनाम राज्य(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)*** मामले में कुछ मापदंडों को समेकित किया है। बालिकाओं से बलात्कार से संबंधित मामलों में जिन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है वे इस प्रकार हैं:

> "42. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इन निर्णयों के अवलोकन से, निम्नलिखित मानदंड और कारक जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए, एक बालिका के साथ बलात्कार के मामलों में स्पष्ट रूप से सामने आते हैं:
>
> ऐसे मामलों को संवेदनशीलता से निपटाने की आवश्यकता है न कि अन्य दंडात्मक अपराधों से जुड़े मामलों की तरह। दूसरे शब्दों में, न्यायालयों का पूरा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होना चाहिए।
>
> यौन अपराधों से जुड़े मामलों में साक्ष्यों की जांच करते समय भारतीय समाज की पारंपरिक गैर-अनुमोदनात्मक सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता में सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

16. वर्तमान मामले में, विद्वान ट्रायल जज ने उपर्युक्त चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि पीड़िता को कुछ दिनों के अंतराल में कम से कम चार बार उसके साथ हुई भयानक घटना

को बताने और दोबारा बताने के लिए कहा गया था; सबसे पहले, घर आने पर अपने पिता/परिवार को; दूसरे, उस पुलिस अधिकारी को जिसने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उसका बयान लिया था; तीसरा, मजिस्ट्रेट को, जिसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया और अंत में, शपथ पर बयान देते समय न्यायालय में। वह एक किशोरी है जो बुरी तरह घायल हो गई थी और उसने खुद को भ्रमित और अर्ध-चेतन अवस्था में पाया। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं थी जिसके लिए उसे अधिकारियों और अज्ञात व्यक्तियों के सामने पूरी घटना को कई बार दोहराया गया और जब वह मानसिक रूप से सदमे की स्थिति में थी और पूरी तरह से अप्रिय उथल-पुथल का सामना कर रही थी, तब उसे तब उसे साक्ष्य देने के लिए कहा गया।

17. भारत जैसे गैर-अनुमोदनात्मक समाज में जहां एक लड़की सामाजिक मानदंडों और परंपराओं से बंधी हुई महसूस करती है, उसके लिए अपने परिवार के साथ ऐसी किसी अप्रिय घटना का विवरण साझा करने से पहले झिझकना स्वाभाविक है, क्योंकि समाज द्वारा उसे अपमानित होने या नीचा दिखने का डर होता है।

18. यदि पीड़िता को मानसिक सदमे से उभरने का उचित समय दिया गया होता तो वह अपना बयान दे सकेंगी और अपने साथ घटी घटना को अधिक सटीक ढंग से याद कर सकेंगी और दोबारा बता सकेंगी। यह एक स्वाभाविक घटना है कि जब हमारा मन और शरीर किसी बड़ी दुर्घटना से गुज़रा हो, तो हमें उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उत्पन्न असमंजस से बाहर निकलने, घटित घटना को समझने और परखने और नई वास्तविकता के साथ जो प्रकरण के बाद शुरू होती है से तालमेल बिठाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इस मामले में, पीड़िता एक युवा लड़की है जिससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उसके पास इतनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गहराई होगी कि वह इतनी तेज गति से पूरी घटना का सामना कर सकेगी और एक असहज और अपरिचित माहौल में बार-बार अपने बयान दे सकेगी।

19. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू होने के बाद, आईपीसी की धारा 376कख के तहत बारह वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के लिए निर्धारित सजा बीस वर्ष से कम नहीं हो सकती है और इसे जुर्माना या मौत के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रावधान में निर्धारित आजीवन कारावास की सजा

को और विस्तृत किया गया है और यह निर्दिष्ट किया गया है कि इसका मतलब उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा जिस पर सजा दी जा रही है। आरोपी द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराध के लिए निर्धारित सजा का दायरा बहुत व्यापक है और ऐसे मामले पर निर्णय सुनाने वाले सत्र न्यायाधीश को इस तथ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है कि मामले का समय पर निपटारा होने पर आरोपी के अधिकार खतरे में न पड़ें। एक तरफ, ट्रायल जज को युवा पीड़िता के अधिकारों के साथ न्याय करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना है कि सुनवाई समय पर और यथासंभव शीघ्रता से की जाए और दूसरी तरफ, ट्रायल जज को इस तरह से तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है ताकि आरोपी के अधिकार खतरे में न पड़ें। दोनों पक्षों के बीच की दूरी न के बराबर है, लेकिन इसे बनाए रखने की आवश्यकता है और न्याय के उल्लंघन से बचने और न्याय के प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारों की दोनों रेखाओं बिना ओवर-लैपिंग या आपस में जुड़े हुए को एक-दूसरे के समानांतर चलने की आवश्यकता है, न्याय प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत यह प्रदान करते हैं कि अधिकारियों को ऐसे तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है जो वैध, उचित और प्रक्रियात्मक रूप से निष्पक्ष हो। यदि वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार किया जाए, तो पीठासीन अधिकारी का आचरण, भले ही उसका इरादा न हो, लेकिन यह अनुचित, प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित और कानून के अनुरूप नहीं था।

20. मामले को जल्द निपटाने की इच्छा में, पीठासीन अधिकारी ने सुनवाई इतनी जल्दबाजी में की कि कई कमियों को नजरअंदाज कर दिया गया या चूक की गई। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करते समय इस न्यायालय द्वारा कई दोष और विरोधाभास देखे गए हैं। उदाहरण के लिए, एफआईआर में यह खुलासा हुआ है कि ग्रामीणों ने पीड़िता को बेहोश, अस्त-व्यस्त और घायल अवस्था में पड़ा हुआ पाया था, जबकि पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता खुद चलकर अपने घर वापस आई थी, उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। अन्य विसंगतियां भी हैं लेकिन यह न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करना चाहता है या गवाहों की गवाही और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों की विश्वसनीयता पर कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहता है, हालांकि, इस न्यायालय की चिंता व्यक्त करने के लिए उपरोक्त टिप्पणी की गई है। विसंगति को दूर करने का कोई

प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि विद्वान ट्रायल जज का बल मुकदमे को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करने पर था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े।

21. रिकॉर्ड से पता चलता है कि न तो न्यायालय ने आरोपी से पूछा कि क्या उसने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अधिवक्ता को नियुक्त किया है या वह एक गरीब व्यक्ति है ताकि उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता को नियुक्त करने का समय दिया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान की जा सके और न ही उसे पर्याप्त सहायता दी गई। दरअसल, आरोपी की ओर से विधिक सहायता के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण में कोई आवेदन नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि उनके मामले की पैरवी के लिए डीएलएसए के एक पैनल अधिवक्ता को उन पर थोप दिया गया है।

22. अभियुक्त को अपने अधिवक्ता से मिलने, उसके साथ बैठने या रणनीति बनाने के लिए कोई समय नहीं दिया गया ताकि वह अधिवक्ता को मामले से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत करा सके। किसी मनोवैज्ञानिक या सिविल सर्जन से उसकी जांच कराने का प्रयास नहीं किया गया। उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के साथ-साथ परिवार/आश्रितों के संबंध में सामाजिक न्याय विभाग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं किया गया है।

23. इतनी जल्दबाजी में पीड़िता का बयान दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जब वह घटना से बुरी तरह डर गई थी और रिपोर्ट के अनुसार, उसी दिन उसकी सर्जरी हुई थी और वह अस्पताल की गहन देखभाल इकाई में थी। इस न्यायालय के विचार में, वह सदमे में थी और प्रश्नावली का उत्तर देने वाले पुलिस अधिकारी, न्यायालय के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी आदि की उपस्थिति उससे कम दर्दनाक नहीं थी जो उसने पहले ही सहन कर लिया था।

24. अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करने हेतु एक अधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश दिनांक 28.09.2021 को पारित किया गया तथा जिला विधिक सहायता प्राधिकरण से एक अधिवक्ता नियुक्त कर अभियुक्त को आरोप-पत्र की प्रति दी गई। उनके समक्ष अपराध का संज्ञान लिया गया और आरोप तय करने पर दलीलें सुनी गईं और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376कख और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा, 2012 की धारा 5/6 के तहत उसी दिन आरोप तय किए गए। यहां तक कि चालान भी शाम 07.30 बजे बिना

कागज के घर पर ही दायर किया गया। 27.09.2021 को; विद्वान न्यायमूर्ति द्वारा 28.09.2021 को संज्ञान लिया गया तथा 30.09.2021 को आठ गवाहों के बयान दर्ज किये गये।

25. एक से अधिक उदाहरणों में, इस न्यायालय को उस अनुचित जल्दबाजी और तात्कालिकता पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो जांच के विभिन्न चरणों के साथ-साथ परीक्षण के प्रभावी चरणों में दिखाई गई थी। जब पीड़िता को दोपहर 02:00 बजे छुट्टी मिलने वाली थी तो उसी दिन अस्पताल में पीड़िता का बयान दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

26. पीड़िता को यह समझने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ था, सांस लेने के समय के रूप में एक छोटा सा कूलिंग पीरियड दिया जाना चाहिए था अपराध को और अधिक सटीक तरीके से और पूरी घटना को बेहतर तरीके से समझ सके ताकि वह घटना के विवरण के साथ-साथ घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण भी साझा कर सके। अभी कुछ समय पहले उनके साथ जो बड़ी दुर्घटना हुई थी और उनकी उम्र के बारे में बयान देते समय उनकी मानसिक स्थिति अस्पष्ट रही होगी।

27. <u>बलात्कार के मामलों की सुनवाई तत्काल होनी चाहिए:</u>

सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित मामले की सुनवाई निरंतर चलनी चाहिए और दिन-प्रतिदिन के आधार पर होनी चाहिए। न्यायालय स्थापित विधिक स्थिति से सहमत है कि एक बार जब गवाहों की जांच का चरण शुरू हो जाता है, तो उपस्थित सभी गवाहों की एक दिन में ही जांच की जानी चाहिए, हालांकि, कई मामलों में ऐसा ही हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक घोषणाएं और उनमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि निष्पक्ष और उचित सुनवाई के लिए दोनों पक्षों में से किसी एक के अधिकारों को तेजी से दोषसिद्धि/बरी करने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी, बल्कि यह प्रचारित किया गया है कि सुनवाई होनी चाहिए अभियोजन और बचाव दोनों के हित में दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ें।

28. एक तरफ, न्यायालय सोचती है कि एक बलात्कार पीड़िता को उसके साथ हुई घटना के सदमे से बाहर आने के लिए समय चाहिए और दूसरी तरफ, घटना घटित होने के पाँच दिनों की अवधि के भीतर उसे अपना बयान दर्ज करने और न्यायालय के सामने गवाही

देने के लिए कहा जाता है।

29. <u>एक ही दिन दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश पारित किया गया:</u>

भगवानी बनाम मध्य प्रदेश सरकार, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह व्यवस्था दी है कि सजा के बिंदु पर अलग से सुनवाई होनी चाहिए ताकि अभियुक्त को जल्दबाजी में अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय और उचित अवसर मिल सके और निचली अदालत द्वारा हत्या और बलात्कार के मामलों में सुनवाई करने में जल्दबाज़ी को भी नोट किया है। हालांकि, इस मामले के तथ्य अलग हैं और इस प्रकार, सजा वर्तमान अपीलार्थी पर लगाई गई सजा से अधिक गंभीर है, लेकिन सजा के लिए अलग सुनवाई के विषय पर राय मौजूदा मामले और उपरोक्त उद्धृत प्रासंगिक पैराग्राफ के लिए प्रासंगिक है। निर्णय इस प्रकार है:

> "13. यह न्याय का मखौल है क्योंकि अपीलार्थी को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया। यह एक उत्कृष्ट मामला है जो ट्रायल कोर्ट द्वारा बलात्कार और हत्या से जुड़े आपराधिक मामलों पर जल्दबाजी में निर्णय देने की परेशान करने वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह घिसा-पिटा कानून है कि एक आरोपी निष्पक्ष सुनवाई का पात्र है जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत है। दोषसिद्धि और सजा के आदेश एक ही दिन पारित होने के संबंध में, धारा 235(2) दंड प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य हेतु यह है अभियुक्त को उसे दी जाने वाली सज़ा के ख़िलाफ़ अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अभियुक्त को प्रभावी अवसर प्रदान करने के लिए दोषी ठहराने और सज़ा सुनाने के लिए द्विभाजित सुनवाई आवश्यक है। मृत्युदंड के प्रश्न पर प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त को प्रदान किया जाएगा।"

30. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उदाहरणों को समेकित करने और इस प्रश्न का एक निश्चित और समान उत्तर खोजने के उद्देश्य से ***2022 के संख्या में सुओ मोटो रिट याचिका (सीआरएल)*** में सुनवाई की कि क्या, दोषसिद्धि दर्ज करने के बाद कानून के तहत मृत्युदंड के अपराध में सजा के बिंदु पर अलग से सुनवाई करना न्यायालय का दायित्व है। इस मामले को एक समान दृष्टिकोण की मांग करते हुए एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था, लेकिन यह देखा गया कि एक बात जो सभी उदाहरणों में आम थी वह यह थी कि *'सार्थक, वास्तविक और प्रभावी'* सुनवाई अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए और आरोपी को सज़ा के निर्णय के लिए प्रासंगिक कोई भी सामग्री प्रस्तुत करना और अपना

बचाव करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

> "22. मनोज और अन्य बनाम मध्य प्रदेश सरकार में दोषसिद्धि के प्रश्न पर पक्षों को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने आरोपी को शमन करने वाली परिस्थितियों को प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए परिवीक्षा अधिकारी, जेल अधिकारियों, एक प्रशिक्षित मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक, आदि, से रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देशों के साथ सजा पर प्रस्तुतिकरण के लिए मामले को स्थगित कर दिया था। इस संबंध में एक समान ढांचे की कमी को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान स्वत: संज्ञान WP (Crl.) संख्या 1/2022 शुरू किया गया था जिसमें इस न्यायालय ने अपने आदेशों द्वारा संकेत दिया है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के तौर-तरीकों पर काम करने की आवश्यकता, शमन करने वाली परिस्थितियों को उजागर करने के लिए साक्ष्य जोड़ने का चरण और इस संबंध में संस्थागत क्षमता बनाने की आवश्यकता है। इस तरह के ढांचे की अनुपस्थिति से संबंधित आशंकाओं को मनोज और अन्य बनाम मध्य प्रदेश सरकार में अंतिम निर्णय में दर्ज किया गया था, जिसमें एक अलग सुनवाई के महत्व और अभियुक्त की पृष्ठभूमि के विश्लेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। यह सुझाव दिया गया था कि मृत्युदंड पर विचार करते समय सामाजिक परिवेश, उम्र, शैक्षिक स्तर, क्या दोषी को जीवन में पहले आघात का सामना करना पड़ा था, पारिवारिक परिस्थितियाँ, दोषी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और सजा के बाद का आचरण प्रासंगिक कारक थे।
>
> 23. उपरोक्त के आलोक में, इस विषय पर तीन न्यायाधीशों की पीठ के दो निर्णयों में स्पष्ट रूप से विचारों का टकराव मौजूद है। जैसा कि पहले देखा गया था, बचन सिंह मामले में इस न्यायालय ने 48वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर अवलंब करते हुए, दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा को बरकरार रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के रूप में, एक अलग सुनवाई द्वारा एक दोषी को प्रदान की गई निष्पक्षता पर विचार किया था। यह भी एक तथ्य है कि उन सभी मामलों में जहां मृत्युदंड देना सजा का एक विकल्प है, गंभीर परिस्थितियां हमेशा रिकॉर्ड पर होंगी, और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का हिस्सा होंगी, जिससे सजा होगी, जबकि अभियुक्त से रिकॉर्ड पर परिस्थितियों को प्रस्तुत करने की, क्योंकि ऐसा करने का चरण दोषसिद्धि के बाद है, शायद ही उम्मीद की जा सकती है। इससे दोषी को निराशाजनक नुकसान होता है और पलड़ा उसके खिलाफ भारी पड़ जाता है। इस न्यायालय की राय है कि सजा के मुद्दे पर अभियुक्त/दोषी को औपचारिक सुनवाई के बजाय वास्तविक और सार्थक अवसर देने के प्रश्न पर एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए मामले में स्पष्टता होना आवश्यक है। "

31. गंभीर परिस्थितियों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है, फिर कम करने वाली

परिस्थितियों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है और उसके बाद, दोनों को रिकॉर्ड पर लिया जाना है, एक-दूसरे के मुकाबले तौलना और मापना है और फिर उसी के संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुंचना है। सज़ा की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से शमन करने वाली और गंभीर करने वाली दोनों परिस्थितियों को सूचीबद्ध करने और एक-दूसरे के विरुद्ध तौलने की आवश्यकता है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त खुद का बचाव करने के उद्देश्य से जिन शमनकारी परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर रखना चाहेगा, उन्हें अपराध का पता चलने और अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के बाद ही बताया जा सकता है, इस प्रकार, एक अलग सुनवाई की आवश्यकता है। सजा के बिंदु पर सीआरपीसी की धारा 235 इस प्रकार है:

> **235. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय।**
> (1) दलीलों और कानून के बिंदुओं (यदि कोई हो) को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति मामले में निर्णय देगा।
> (2) यदि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायमूर्ति, जब तक कि वह धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार आगे नहीं बढ़ता, सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा, और फिर कानून के अनुसार उसे सजा सुनाएगा।

32. धारा 235 के उप-खंड (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक बार अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के बाद, उसे सजा के प्रश्न पर सुना जाएगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी। यह तर्क कि, यदि धारा 235 की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि यह अनिवार्य नहीं है कि दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश एक ही दिन पारित नहीं किया जा सकता है, तब भी, दोषसिद्धि का निर्णय पारित करने के बाद और पारित करने से पहले अभियुक्त को सुनने की आवश्यकता होती है। सज़ा का क्रम क़ानून में स्पष्ट है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता। अभियुक्त की सुनवाई एक प्रभावी सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि सजा की प्रक्रिया को एक ऐसा चरण नहीं माना जा सकता है जो अभियुक्त के अपराध को तय करने के चरण के अधीन है।

33. इस न्यायालय के विचार में, दोषसिद्धि का निर्णय पारित होने के बाद उचित समय की आवश्यकता होती है और इसके दो कारण हैं:

i) 6 सजा का आदेश पारित करने से पहले कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जैसे अपराध की प्रकृति, बढ़ाने/कम करने और गंभीर करने वाली परिस्थितियां, पिछली

आपराधिक पृष्ठभूमि, अपराध करने वाले व्यक्ति की उम्र, आरोपी की शैक्षिक पृष्ठभूमि, जानकारी अभियुक्त के रोजगार, अपराधी की मानसिक और भावनात्मक स्थिति, घर और परिवार में अपराधी का जीवन, "समाज और सामाजिक समायोजन, अपराधी के पुनर्वास की संभावनाएं, अपराधी के सामान्य जीवन में लौटने की संभावना" से संबंधित समुदाय में, अपराधी के उपचार या प्रशिक्षण की संभावना, यह संभावना कि सजा अपराधी या अन्य लोगों द्वारा किए गए अपराध के लिए एक निवारक के रूप में काम कर सकती है और वर्तमान समुदाय अपराध के प्रकार को विशेष के संबंध में ऐसे निवारक की आवश्यकता है, यदि कोई हो।" किसी भी अधिवक्ता के लिए सजा के बिंदु पर सुनवाई की तैयारी करना और किसी भी न्यायमूर्ति के लिए विचार करना, इन कारकों के बारे में प्रस्तुतियाँ करने और सजा का आदेश पारित करने के लिए, इस पहलू पर उचित मात्रा में समय नियोजित करना होगा। वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, आरोपी-अपीलार्थी के अधिवक्ता को उपरोक्त सूचीबद्ध कारकों पर जानकारी प्रस्तुत करने या प्राप्त करने का समय भी नहीं मिला, उस पर उत्तर देने या प्रस्तुत करने के लिए तैयार होना तो दूर की बात है। ऐसी परिस्थितियों में, यह अनुमान लगाना असुरक्षित होगा कि वर्तमान मामले के अपराधी को सजा के बिंदु पर प्रस्तुतियाँ देने के लिए वास्तव में एक उचित अवसर प्रदान किया गया था और इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 235 के तहत निहित आदेश विशेष रूप से तब समाप्त हो जाता है मृत्युदंड या संपूर्ण प्राकृतिक जीवन के शेष रहने तक या आजीवन कारावास जब सजा सुनाई जाती है।

ii) भले ही यह माना जाता है कि एक ही दिन की सजा के मामलों में पर्याप्त समय प्रदान किया जाता है, यह धारणा कि सजा उसी दिन पारित की गई थी जिस दिन दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया था, इस बात पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है कि क्या ऊपर चर्चा किए गए कारक सही थे। इस पर विचार किया गया या नहीं.

34. <u>मुकदमा चलाने में जल्दबाजी:</u>

इंग्लैंड के तत्कालीन लॉर्ड चीफ जस्टिस, लॉर्ड हेवर्ट ने रेक्स बनाम ससेक्स जस्टिस; एक्स पार्टी मैक्कार्थी [1924] 1 केबी 256 में प्रकाशित प्रसिद्ध उक्ति दी थी कि 'न्याय होते हुए दिखना चाहिए'। 'न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से और निस्संदेह किया हुआ दिखना भी चाहिए।' अक्सर उद्धृत किया जाने वाला यह ऐतिहासिक

वाक्यांश लगभग सौ वर्षों से प्रचलन में है। यह एक दिलचस्प मामला था जहां न्यायमूर्तियों का क्लर्क उस फर्म में भागीदार था जो पक्षों में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहा था और विरोधी पक्ष ने इस तथ्य का विरोध किया था कि उक्त क्लर्क न्यायमूर्तियों के साथ सेवानिवृत्त हुआ था। बाद में, यह स्पष्ट किया गया और तथ्य की बात के रूप में कहा गया कि क्लर्क ने मामले के संबंध में किसी भी चर्चा में भाग नहीं लिया, हालांकि, लॉर्ड हेवार्ट ने मामले में पारित दोषसिद्धि को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वास्तव में क्या किया गया था यह महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन क्या दिखाई दे सकता है किया गया महत्वपूर्ण है और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:

> "ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे यह संदेह भी पैदा हो कि न्याय की प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप हुआ है।"

35. इस मामले में कोरम का गठन करने वाले अन्य न्यायामूर्तियों में से एक ने न्यायमूर्ति हेवार्ट से सहमति व्यक्त की और उन्होंने कहा कि भले ही ट्रायल जजों द्वारा कुछ भी अनियमित या गलत करने का इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने क्लर्क को न्यायाधीशों के साथ सेवानिवृत्त होने की अनुमति देकर अधिवक्ता द्वारा उनकी उपस्थिति को माफ किए बिना खुद को बिना किसी जीत की स्थिति में डाल दिया। इसी प्रकार, मौजूदा मामले में, इस न्यायालय को नहीं लगता कि विद्वान निचली जज ने किसी अन्य गुप्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जल्दबाजी में काम किया है, फिर भी रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि अंतिम निपटान का कार्य उनके द्वारा सिर्फ एक दृष्टिकोण से किया गया था कि मामले का यथाशीघ्र निपटारा करें ताकि वीभत्स घटना के पीड़िता को न्याय मिल सके। यहां, विद्वान ट्रायल जज का इरादा कुछ अनियमित या गलत करने का नहीं रहा होगा, हालांकि, उन्होंने खुद को एक असंभव स्थिति में डाल दिया, जिसमें अगर ट्रायल आयोजित करने की समयसीमा और तरीके की जांच संहिता के प्रक्रियात्मक प्रावधानों के खिलाफ की जाती है। आपराधिक प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की रचनात्मक रूप से व्याख्या की गई छत्रछाया में आते हैं, तो यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तव में जो किया गया है वह अपना महत्व खो देगा, चाहे जो भी हो इस तथ्य की जांच करना कि क्या यह सही था या गलत, और जो किया गया प्रतीत होता है वह महत्वपूर्ण होगा।

36. न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के उन आदेशों को रद्द करने में इस

सुस्थापित सिद्धांत का उपयोग, जिनमें भारतीय न्यायालय द्वारा कुछ अनियमित या अनुचित या अनुचित तरीके से किया गया प्रतीत होता है, समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसे अनदेखा करना यह न्यायपालिका की निष्पक्षता में लोगों के विश्वास को हिला सकता है।

37. परीक्षण के विभिन्न चरणों और कदमों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

क्र.सं.	**तारीख**	**विवरण**
1.	26.09.2021	जब घटना घटी
2.	27.09.2021	एफआईआर दर्ज आरोपी गिरफ्तार. सभी जांच की गई और आरोपी को आरोप-पत्र के साथ पुलिस द्वारा शाम 07:00 बजे न्यायालय के समय के बाद पीठासीन अधिकारी के समक्ष उनके आवास पर प्रस्तुत किया गया।
3.	28.09.2021	आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में आदेश पत्र निकाला गया।
		आरोपियों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए डीएलएसए के माध्यम से अधिवक्ता नियुक्त किया गया।
		अधिवक्ता ने आदेश संख्या 171 दिनांक 28.09.2021 की एक प्रति प्रस्तुत की जिसके द्वारा उन्हें डीएलएसए द्वारा नियुक्त किया गया था।
		आरोपियों को दी गई आरोप-पत्र की प्रति।
		संज्ञान के बिंदु पर और आरोप के प्रश्न पर विचार के लिए दलीलें सुनी गईं और तदनुसार, संज्ञान लिया गया और आरोप तय किए गए। उसी दिन मुकदमा शुरू हुआ।
		अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू- 1, 3, 5, 6 और 7 को 29.09.2021 को अपने शपथ पर बयान की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया। अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू- 2, 4, 9, 10 और 11 को 30.09.2021 को अपने शपथ पर बयान की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया।
		अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू- 8, 12, 13, 14 और 15 को 01.10.2021 को अपने शपथ पर बयान की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया। अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू- 16, 17 और 18 को 04.10.2021 को अपने शपथ पर बयान की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया।
4.	29.09.2021	पीडब्लू-1, 2, 3 और 4 के बयान दर्ज किए गए। विशेष पी.पी. ने सूची से गवाह 3 एवं 5 संख्या के नाम हटा दिए गए।
5.	30.09.2021	अभियोजन पक्ष द्वारा दायर तीन आवेदनों पर सुनवाई की गई।

		डॉ. अमन चौधरी को गवाह नंबर 19 के रूप में अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची में जोड़ा गया।
		पीडब्लू- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के शपथ पर बयान दर्ज किए गए।
		एसएचओ, कोटखेड़ा को 01.10.2021 को अस्पताल में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।
6.	01.10.2021	पीडब्ल्यू-13 का बयान दर्ज किया गया।
		पीडब्लू-14 (पीड़िता) का बयान डॉ. अर्पणा, सचिव, डीएलएसए और अस्पताल में पीड़िता की मां की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किया गया।
		सचिव, डीएलएसए द्वारा अदालत को भेजे गए पीड़िता के बयान वाले लिफाफे।
		पीड़िता को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
	02.10.2021	छुट्टी
	03.10.2021	छुट्टी
7.	04.10.2021	पीडब्लू-15 और 16 के बयान दर्ज किए गए।
		धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी से स्पष्टीकरण मांगा गया
		मामला 05.10.2021 को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया।
		अंतिम दलीलें सुनी गईं।
8.	05.10.2021	दोषसिद्धि का निर्णय और सज़ा का आदेश खुली अदालत में लिखा और सुनाया गया।

38. चार्ट से यह स्पष्ट है कि जांच एक दिन से भी कम समय में समाप्त हो गई और आरोप-पत्र दायर किया गया। 28.09.2021 को संज्ञान लेने और आरोप तय करने के बाद मुकदमा शुरू हुआ। कुल चार दिनों में सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लिया गया और पांचवें दिन अंतिम दलीलें सुनी गईं। पांचवें दिन ही खुली अदालत में दोषसिद्धि का निर्णय लिखा और सुनाया गया। मुकदमे के पांचवें दिन आरोप तय करने के बाद सजा का आदेश भी पारित कर दिया गया। प्रभावी रूप से, दो दिनों की छुट्टियों, अर्थात 02.10.2021 और 03.10.2021 को छोड़कर, आरोप तय होने के बाद केवल पांच दिनों की अवधि के भीतर मुकदमा समाप्त हो गया।

39. चार्ट से यह भी परिलक्षित होता है कि घटना की तिथि 26.09.2021 थी; जांच एक दिन के भीतर पूरी की गई और 27.09.2021 को आरोप-पत्र दायर किया गया और उसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें विधिक मदद लेने या उस मामले में

कोई मदद लेने का समय नहीं मिला, क्योंकि उन्हें 28.09.2021 को ही न्यायिक हवालात से न्यायालय ले जाया गया था। उन्हें अपने परिवार या किसी अन्य व्यक्ति से बात करने या अपनी पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने का मौका भी नहीं मिला और इस परेशान करने वाली स्थिति में, उन्हें उचित बचाव के बिना मुकदमे में खड़ा होना पड़ा। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या न्यायालय ने उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए अपने अधिवक्ता से बात करने का अवसर दिया था या क्या अधिवक्ता को उनसे मिलने के लिए जेल में अनुमति दी गई थी या क्या अधिवक्ता के साथ बातचीत करने के लिए उन्हें कोई कमरा आवंटित किया गया था या नहीं।

40. न्यायालयों द्वारा पारित आदेश/निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए, जिनमें से एक 'ऑडी अल्टरम पार्टेम' है। इसका सीधा सा अर्थ है 'दूसरे पक्ष को सुनें'। सिद्धांत यह निर्देश देता है कि किसी भी आदेश/निर्णय को पारित करने से पहले दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की बिना सुने निंदा नहीं की जानी चाहिए। सुनवाई का अवसर वास्तविक होना चाहिए और यह महज औपचारिकता नहीं हो सकता या सिर्फ इसके लिए नहीं दिया जा सकता। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई के लिए पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना है और यह पूर्वाग्रह के खिलाफ कार्य करने वाला और न्यायाधीशों पर निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत तरीके से कार्य करने का सामान्य कर्तव्य लगाने वाला नियम है। इस सिद्धांत का प्रारंभिक सूक्ति है 'क्वी एलिक्विड स्टैट्यूरिट पार्ट इनॉडिटा अल्टेरा, एक्वम लिसेट डिक्सेरिट, हौड एक्वम फ़ेसेरिट' जिसका अर्थ यह है कि 'वह जो दूसरे पक्ष को सुने बिना कुछ भी निर्णय लेता है, भले ही वह सही निर्णय ले सकता है, किसी भी तरह से नहीं न्यायपूर्वक कार्य किया है।'7. प्राचीन युग में भी, कानून का शासन सामाजिक न्याय/प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के साथ-साथ संचालित होता था। न्याय निष्पक्षता की अवधारणा है और सामाजिक न्याय निष्पक्षता है क्योंकि यह समाज में मौजूद/प्रदर्शित है, इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कुछ और नहीं बल्कि वे हैं जो स्वाभाविक रूप से उचित या अनुचित सही या गलत के बीच अंतर करते हैं। ऐसे समाज में जहां सामाजिक न्याय लागू है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण नहीं किया जा सकता है। सामाजिक न्याय भारत के संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है।8 हमारे जैसे कल्याणकारी संप्रभु में, सामाजिक न्याय के सिद्धांत का अर्थ यह होगा कि

समाज में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और असंतुलन की समस्या का आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए विधायिका और कानून के शासन द्वारा बनाये गए कानूनों की मदद से सामना किया जाएगा। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, न तो अति-विनियमन और अति-कानून द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा सकता है और न ही किसी व्यक्ति को बिना किसी उचित विनियमन के कार्य करने या अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी जा सकती है। इसलिए, आपराधिक कार्यवाही में पक्षकार होने के कारण यह अभियुक्त का अधिकार है कि उसकी बात सुनी जाए ट्रायल जज द्वारा निष्पक्ष तरीके से सुनी जाए और उसे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर आवश्यक चरण में उचित अवसर प्रदान किया जाए।

41. इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, सुनवाई का अवसर तब दिया गया माना जाएगा जब दोनों पक्षों के पास आपराधिक कार्यवाही के प्रक्रियात्मक कदमों का पालन करने और मुकदमे के किसी भी चरण में अपने तर्क और बचाव तैयार करने के लिए पर्याप्त समय हो। दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा मुकदमा चलाना आवश्यक और अनिवार्य है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वे अभियुक्तों के अधिकारों को कुचलने के क्योंकि किसी मुकदमे के निपटारे के बीच खींची गई पतली रेखा को अनावश्यक देरी के बिना पार करना बहुत आसान है। कानून के आदेश के अनुसार और न्याय प्रदान करने और आपराधिक कार्यवाही के अंतिम निर्णय में अति-उत्साह प्रति सतर्क रहें। जब आखिरकार आपराधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता/व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती से संबंधित मामले हैं जो किसी भी सभ्यता में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट के लिए निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से सुनवाई करना और दोनों पक्षों के अधिकारों का ध्यान रखना आवश्यक है ।

42. जब साध्य के साधन उचित नहीं हैं, तो साध्य को उचित नहीं कहा जा सकता। साधन और तरीका उचित नहीं थे इसलिए निष्कर्ष को निष्पक्ष और उचित निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। मुकदमे का निष्कर्ष एक उचित निष्कर्ष हो सकता है, लेकिन यदि इसे ऐसी प्रक्रिया और तरीके से हासिल किया गया है जो उचित नहीं है और कानून और न्याय की भावना तथा निष्पक्ष प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है तो परिणाम को अच्छा परिणाम नहीं कहा जा सकता है। यह गलत नहीं समझा जाना चाहिए कि यह न्यायालय निचली अदालत द्वारा

दिए गए निष्कर्ष की सत्यता पर टिप्पणी कर रहा है या मामले की गुणागुण के आधार पर दोषसिद्धि को पलट रहा है, बल्कि इस न्यायालय की चिंता यह है कि जिस तरीके और ढंग से मुकदमा चलाया गया। अन्याय को बढ़ावा नहीं देगा। यदि न्यायिक निदान के परिणाम तक पहुँचने के लिए अपनाई जाने वाली तरिके कानून और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं, तो परिणाम को उचित नहीं कहा जा सकता है। एक व्यक्ति परिवार की एक इकाई है; परिवार समाज की एक इकाई है और कानून समाज के लिए बनाया गया है और यह सामाजिक भलाई के इर्द-गिर्द घूमता है, इस प्रकार, यदि आरोप गंभीर प्रकृति का है, तो आरोपी को अपने रुख या अधिकारों का बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा अवसर वास्तविक होना चाहिए न कि केवल एक ऐसा प्रयास जिसे दृश्य प्रयास के रूप में देखा जाए।

43. परीक्षण न्यायाधीशों के बीच यह देखने के लिए कोई दौड़ या प्रतियोगिता नहीं है कि कौन पहले समाप्त करता है या किसने पहले परीक्षण समाप्त किया है। न्याय को उस तरह के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। शिकायतकर्ता के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की रक्षा करते समय, न्यायालय को दुर्भावना से पैदा हुए मुकदमे या गलत तरीके से किए गए मुकदमे से आरोपी के बचाव के अधिकार के प्रति सचेत रहना होगा। अनुचित जल्दबाजी और अनुचित देरी के बीच संतुलन बनाते हुए नियमित, व्यवस्थित तरीके से परीक्षण करने के लिए बीच में एक रास्ता निकालने की आवश्यकता है।

44. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 में कार्यवाही को स्थगित या स्थगित करने की शक्ति शामिल है। प्रावधान का पहला उप-खंड इस प्रकार है:

> **309. कार्यवाही स्थगित या स्थगित करने की शक्ति** - (1) प्रत्येक जांच या मुकदमे में कार्यवाही दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रखी जाएगी जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की जांच नहीं हो जाती, जब तक कि न्यायालय अगले दिन से आगे के स्थगन को रिकॉर्ड किए गए कारणों से आवश्यक न समझे:
>
> बशर्ते कि जब जांच या मुकदमा धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा डीबी के तहत किसी अपराध से संबंधित हो, तो जांच या आरोप-पत्र दायर होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर मुकदमा पूरा किया जाएगा।

45. उपरोक्त प्रावधान का एक सरल अर्थ यह समझ में आता है कि कार्यवाही दिन-प्रतिदिन के

आधार पर की जाएगी और गवाहों की सूची के अंत तक पहुंचने और प्रत्येक गवाह की जांच होने तक जारी रहेगी, हालांकि, यह कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसा ऐसे तरीके से किया जाएगा जो अनुचित और अतार्किक हो। धारा 309 में निहित राइडर आगे निर्दिष्ट करता है कि आईपीसी की धारा 376कख के तहत अपराध से संबंधित मुकदमे को आरोप-पत्र दायर करने की तारीख से दो महीने की समयावधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि क़ानून त्वरित सुनवाई पर विचार करता है, लेकिन मुकदमे के निपटान के लिए अभियुक्त को शीघ्र जांच करने की कीमत पर नहीं, ताकि जितनी जल्दी हो सके न्याय प्रदान किया जा सके।

46. तात्कालिकता की सीमा ऐसी नहीं थी कि पुलिस ने एक ही दिन में जांच पूरी कर ली, क्योंकि 27.09.2021 को एफआईआर दर्ज हुई और उसी दिन पुलिस ने पीठासीन अधिकारी के आवास पर चालान प्रस्तुत कर दिया। न तो ऐसा मामला था कि सीआरपीसी की धारा 167 के तहत निर्धारित नब्बे दिनों की समयावधि समाप्त होने वाली थी और न ही ऐसा मामला था कि कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला था या उस मामले के लिए, मामले की परिस्थितियों में किसी भी बदलाव का कोई मतलब नहीं था। पुलिस ने अगले दिन न्यायालयिक समय/उचित कार्य घंटों में पीठासीन अधिकारी के समक्ष चालान प्रस्तुत करने का इंतजार नहीं किया।

47. त्वरित न्याय वैधानिक प्रक्रिया एवं स्थापित परंपराओं के अनुपालन में न किये जाने पर कमजोर न्याय बन जाता है। यदि अभियुक्त अपराध करने का दोषी है तो मुकदमा शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए ताकि गवाहों की याददाश्त धुंधली न हो, लेकिन वर्तमान मामले में, बयान और गवाही बहुत तेजी से दर्ज की गईं, जिसके कारण पीड़ित के साथ-साथ अभियुक्त के मुकदमे के अधिकार को बाधित करना जो न्याय, निष्पक्षता और पूर्वाग्रह से मुक्ति द्वारा चिह्नित है पुन: आघात हुआ।

48. किसी भी अन्याय, पूर्वाग्रह, अनुचितता या मनमानी के बिना एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए हाई-स्पीड ट्रायल और निःशुल्क विधिक सहायता दो पूर्व-आवश्यकताएँ हैं। हाई-स्पीड ट्रायल की आवश्यकता पर पहले ही पूर्ववर्ती पैराग्राफ में पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है, इसलिए, यह न्यायालय अब निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता पर आगे बढ़ेगा। अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार भारत के संविधान में निहित है। अनुच्छेद 21

में प्रावधान है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी को भी उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा और अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के विधिक व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 39ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है और इसे आसान संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> **39क. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।** राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य विकलांगताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए।

49. अनुच्छेद 39ए में न्याय हासिल करने के अवसरों का उल्लेख है जिससे किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाना चाहिए और केवल मानदंडों के अनुपालन के लिए उचित विधिक सहायता या विधिक सहायता का प्रावधान न करना ऐसे अवसर से इनकार करने के समान है। वर्तमान मामले में, अभियुक्त को अपना अधिवक्ता चुनने का उचित अवसर नहीं दिया गया है और भले ही यह माना जाता है कि प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई विधिक सहायता अभियुक्त का बचाव करने के लिए पर्याप्त और अच्छी तरह से सुसज्जित थी, वास्तव में, अधिवक्ता द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अभियुक्त को वास्तविक परामर्श लेने का अवसर नहीं मिला। अभियुक्त के लिए सच्चे और आवश्यक अधिवक्ता में आदर्श रूप से अभियोजन के मामले को तोड़ना, अभियुक्त के लिए एक अच्छा मामला बनाना और वैध बचाव का बनाना शामिल होगा, जिनमें से कुछ भी अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया था। वैधानिक आवश्यकता के अनुसार प्रदान की गई अधिवक्ता की सहायता को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है यदि ऐसी सहायता पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थी या परीक्षण के प्रत्येक प्रभावी मोड़ पर अभियुक्त को संतोषजनक ढंग से प्रदान नहीं की गई थी।

50. अनुच्छेद 39क के अलावा, सीआरपीसी की धारा 41घ भी आरोपी को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार देती है, हालांकि जांच के पूरे समय

नहीं। मौजूदा मामले में आरोपी सीआरपीसी की धारा 41घ के तहत उसे मिले अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाया है। सीआरपीसी की धारा 41घ इस प्रकार है:

> **41घ. गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार**.- जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ की जाती है, तो वह पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का पात्र होगा, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं।

51. जिरह के अधिकार पर चर्चा शुरू करने से पहले सीआरपीसी की धारा 303 और 304 पर चर्चा करना उचित समझा जाता है। सीआरपीसी की धारा 303 और 304 के तहत प्रावधानों को नीचे दोहराया गया है:

> **303. उस व्यक्ति का बचाव करने का अधिकार जिसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है**-कोई भी व्यक्ति जिस पर आपराधिक न्यायालय के समक्ष अपराध का आरोप लगाया गया है, या जिसके खिलाफ इस संहिता के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, उसका बचाव उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा किया जा सकता है।
>
> **304. कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के खर्च पर विधिक सहायता।**
>
> (1) जहां, सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे में, अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाता है, और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो न्यायालय राज्य के खर्चे पर उसके रक्षा लिए एक अधिवक्ता नियुक्त करेगा।
>
> (2) उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, निम्नलिखित के लिए नियम बना सकता है -
>
> (ए) उपधारा (1) के तहत बचाव के लिए अधिवक्ताओं के चयन का तरीका;
>
> (बी) न्यायालयों द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाएं;
>
> (सी) सरकार द्वारा, और आम-तौर पर, उप-धारा (1) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे अधिवक्ताओं को देय फीस।
>
> (3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि, अधिसूचना में निर्दिष्ट तारीख से, (1) और (2) उप-धाराओं के प्रावधान राज्य में अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी भी वर्ग के मुकदमों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सत्र न्यायालयों के समक्ष मुकदमों के संबंध में लागू होते हैं।

52. जब विधायी मंशा को किसी विशिष्ट प्रावधान के रूप में संहिता में शामिल किया जाता है,

तो इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जिससे प्रावधान निरर्थक हो जाए और प्रावधान का उद्देश्य पूरा न हो। प्रावधान में 'बचाव' शब्द में उचित और तार्किक अवसर के साथ प्रभावी बचाव शामिल है। अभियुक्तों के बचाव के अधिकार का प्रावधान महज कागजी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त प्रावधान अभियुक्त के अपनी पसंद का अधिवक्ता चुनने के अधिकार के बारे में बात करते हैं यदि वह किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष किसी अपराध के आरोप का सामना कर रहा है या आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत शुरू की गई किसी कार्यवाही का सामना कर रहा है। निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की गारंटी न केवल भारत के संविधान द्वारा दी गई है, बल्कि यह आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून निर्धारित करने वाले कानून में भी स्पष्ट है।

53. आगे बढ़ते हुए, जिरह के अधिकार पर चर्चा की जानी चाहिए। किसी मुकदमे में गवाहों से जिरह करने का बचाव का अधिकार किसी व्यक्ति के शरीर में काठ की रीढ़ के समान है। बचाव तंत्र का समर्थन करना और अभियुक्त के खुद का बचाव करने और अपनी पुष्टि के लिए मामला स्थापित करने के अधिकार की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 'मुख्य परीक्षा', 'प्रतिपरीक्षा' और 'पुनः परीक्षा' को परिभाषित करती है और धारा 138 परीक्षाओं के क्रम का वर्णन करती है। इन दोनों धाराओं को एक साथ पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी परीक्षा बिना जिरह के पूरी नहीं मानी जा सकती, सिवाय इसके कि जब विरोधी पक्ष स्वयं किसी गवाह या गवाहों से जिरह नहीं करना चाहता हो और जिरह एक अभियुक्त का स्वतंत्र अधिकार है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 और 138 को आसान संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> **137. मुख्य परीक्षा** - गवाह को बुलाने वाले पक्ष द्वारा की गई परीक्षा को उसका मुख्य परीक्षा कहा जाएगा।
>
> **जिरह** -प्रतिपक्ष द्वारा किसी गवाह की जांच उसकी जिरह कहलाएगी।
>
> **पुन:परीक्षा** - किसी गवाह की जिरह के बाद उसे बुलाने वाले पक्ष द्वारा की गई जांच को उसकी दोबारा जांच कहा जाएगा।
>
> **138. परीक्षाओं का क्रम** - गवाहों से पहले मुख्य रूप से पूछताछ की जाएगी, फिर (यदि विरोधी पक्ष ऐसा चाहता है) जिरह की जाएगी, फिर (यदि उसे बुलाने वाला पक्ष ऐसा चाहता है) फिर से जांच की जाएगी।
>
> परीक्षा और जिरह प्रासंगिक तथ्यों से संबंधित होनी चाहिए, लेकिन जिरह उन तथ्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए जिनके बारे में गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में गवाही दी थी।

> **पुन: परीक्षण की दिशा**- पुन: परीक्षण का उद्देश्य जिरह में संदर्भित मामलों की व्याख्या करना होगा; और, यदि न्यायालय की अनुमति से नया मामला पुन: परीक्षण में प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिकूल पक्ष उस मामले पर आगे जिरह कर सकता है।

54. धारा 138 में यह भी निर्धारित है कि परीक्षा और जिरह दोनों प्रासंगिक तथ्यों से संबंधित होने चाहिए, हालांकि, जिरह उन तथ्यों तक सीमित नहीं है जिनकी गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा के दौरान गवाही दी थी। वर्तमान मामले में, अधिवक्ता और अभियुक्त के पास एक-दूसरे के साथ संवाद करने और बचाव की रणनीति विकसित करने या मामले और मामले में प्रचलित परिस्थितियों के बारे में विवरण साझा करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था क्योंकि आरोप-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष अदालती समय के बाद शाम के 7.00 बजे अपने आवास पर प्रस्तुत किया गया था और डीएलएसए के अधिवक्ता को आदेश संख्या 171 दिनांक 28.09.2021 के तहत नियुक्त किया गया था और इस प्रकार, चालान कागजात की एक प्रति उन्हें 28.09.2021 को ही प्रदान की गई थी। उसी दिन, संज्ञान के बिंदु के साथ-साथ आरोप के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ संज्ञान लिया गया और आरोप भी तय किए गए। उम्मीद के मुताबिक, अधिवक्ता के पास खुद को आरोप-पत्र से ठीक से परिचित होने का समय नहीं हो सका, अपने मुवक्किल अर्थात आरोपी-अपीलार्थी को तो छोड़ ही दें। 28.09.2021 को आरोप तय होने के बाद चार दिनों की सुनवाई के भीतर, मामले का निर्णय अंततः 05.10.2021 को शिकायतकर्ता के पक्ष में किया गया। मुकदमे के संचालन में अनावश्यक जल्दबाजी और गवाहों से जिरह करने की क्षमता के कारण अधिवक्ता को अभियुक्त से घटना के बारे में जानने या कहानी का उसका पक्ष सुनने का पर्याप्त मौका नहीं मिला और गवाहों से जिरह करने की क्षमता के प्रतिकूल प्रभाव से बच नहीं सके। यह जल्दबाजी इस बात की शायद ही कोई संभावना है कि अधिवक्ता को ऐसे तथ्यों की जानकारी थी, जिनकी गवाहों ने अपनी जांच के दौरान गवाही नहीं दी होगी, ताकि सीआरपीसी की धारा 138 के तहत निर्धारित सीमा से परे जिरह की जा सके।

55. ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अभियुक्त के दृष्टिकोण से चर्चा करने और कोई भी जानकारी साझा करने का अवसर नहीं मिला जिसके बारे में अभियुक्त चाहता था कि उसका अधिवक्ता अवगत हो, इस प्रकार, इसे पचाना

मुश्किल है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अभियुक्त को जो सहायता प्रदान की गई थी, वह गवाहों से जिरह करने के लिए पर्याप्त जानकारी से सुसज्जित थी या भले ही वह गवाहों से प्रभावी जिरह करने के लिए मामले से पर्याप्त परिचित था।

56. यह न्यायालय **सुनील बनाम सरकार** नामक मामले में हाल ही में पारित निर्णय से दिल्ली उच्च न्यायालय के शब्दों को उधार लेना चाहेगा, जो इस प्रकार है:

> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी आपराधिक मामले में गवाहों को बदनाम करने और बयान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए किसी भी आरोपी से जिरह करने का अधिकार आपराधिक मुकदमे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।"

57. यदि अधिवक्ता उन तथ्यों को जानता है जो आरोप-पत्र में नहीं हैं, तभी वह गवाहों से इस तरह से जिरह कर सकता है जिससे उनकी विश्वसनीयता हिल सकती है या यदि गवाहों को सिखाया जाता है, तो वे सबसे पहले जो बात उनके मन में सामने आती है, उसका उत्तर दे सकते हैं, उन उत्तरों के बजाय, जिनके लिए वे तैयार थे। विद्वान ट्रायल जज को निःशुल्क विधिक सहायता के महत्व को समझना चाहिए था और यह सुनिश्चित करके आरोपी के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था कि अपीलार्थी को ट्रायल के सभी चरणों में प्रभावी विधिक सहायता मिले।

58. भारत के संविधान के अनुच्छेद 39-क में निर्धारित निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार मुकदमे की प्रक्रिया को निष्पक्ष और उचित बनाने के लिए आवश्यक माना जाता है और इस प्रकार, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्यात्मक परिधि का हिस्सा है, जो हर व्यक्ति को दिया गया मौलिक अधिकार है। भारतीय न्यायपालिका में मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के सेनानियों में से एक, न्यायमूर्ति भगवती ने हुसैनारा के अक्सर उद्धृत निर्णय में राय दी थी। ***खातून और अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार सरकार, पटना*** इस प्रकार है:

> "7. हम मौलिक संवैधानिक निर्देश अनुच्छेद 39-क का भी उल्लेख कर सकते हैं जो इस प्रकार है:
>
> 39-क. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण

किसी भी नागरिक को न्याय पाने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए।

यह अनुच्छेद इस बात पर भी बल देता है कि निःशुल्क विधिक सेवा 'उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण' प्रक्रिया का एक अपरिहार्य तत्व है, इसके बिना आर्थिक या अन्य विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्ति न्याय हासिल करने के अवसर से वंचित हो जाएगा।

इसलिए, निःशुल्क विधिक सेवाओं का अधिकार स्पष्ट रूप से किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के लिए 'उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण' प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है और इसे अनुच्छेद 21 की गारंटी में अंतर्निहित माना जाना चाहिए। यह प्रत्येक का संवैधानिक अधिकार है आरोपी व्यक्ति जो गरीबी, निर्धनता या संपर्क रहित स्थिति जैसे कारणों से अधिवक्ता नियुक्त करने और विधिक सेवाएं प्राप्त करने में असमर्थ है और मामले की परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार राज्य को आरोपी व्यक्ति को अधिवक्ता प्रदान करने का आदेश दिया गया है। यह न्याय की आवश्यकता है, बशर्ते आरोपी व्यक्ति ऐसे अधिवक्ता के प्रावधान पर आपत्ति न करे। ..."

59. ***हुसैनारा खातून*** (सुप्रा.) से पहले भी, यह ***माधव हयावदानराव होसकोट बनाम महाराष्ट्र सरकार*** में देखा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित वाक्यांश 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जो निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत है। उसमें यह भी देखा गया कि निष्पक्ष प्रक्रिया के दो घटक हैं, एक प्राकृतिक न्याय और दूसरा एक कैदी के लिए न्याय का अन्य घटक एक अधिवक्ता की सेवाएं हैं जो आपराधिक मुकदमे के चरणों से गुजरने के लिए आवश्यक हैं। उपर्युक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

"11. हममें से एक ने अपनी अलग राय में पेर कृष्णा अय्यर, जे. को 337, 338 पर देखा:

"कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया", अपनी घातक क्षमता के साथ, जीवन और स्वतंत्रता को एक अनिश्चित खिलौना बना देगी यदि हम उन वजनदार शब्दों में कानून का एक विशेषण नियम, अपनी आत्मा में सभ्य, अपने दिल में निष्पक्ष और उनको ठीक करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। प्रक्रियात्मक सुरक्षा की अनिवार्यताएँ अनुपस्थित हैं, जिसके कारण प्रक्रियात्मक पूँछ वास्तविक सिर हिला देगी। क्या मानव अधिकार का पवित्र सार, जिसे सुरक्षित करने के लिए 'करो या मरो' वाली देशभक्ति के साथ मुक्ति के लिए संघर्ष शुरू किया गया था, को आवश्यक मानकों की परवाह किए बिना, औपचारिक और फरीसी नुस्खे द्वारा समाप्त किया जा सकता है? एक अधिनियमित प्रेत एक संवैधानिक भ्रम है। प्रक्रियात्मक न्याय स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 21 पर आधारित है।

वह प्रक्रिया जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले मौलिक अधिकार को विनियमित करने, प्रतिबंधित करने या यहां तक कि अस्वीकार करने के तौर-तरीकों से संबंधित है, निष्पक्ष होनी चाहिए, मूर्खतापूर्ण नहीं, सावधानीपूर्वक मूल अधिकार को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, न कि नष्ट करने के लिए। इस प्रकार समझा जाए तो, 'प्रक्रिया' को किसी भी मनमानी, अजीब या विचित्र बात से इंकार करना चाहिए। एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार को केवल सभ्य प्रक्रिया द्वारा ही प्रसारित किया जा सकता है.... जो मौलिक है वह जीवन और स्वतंत्रता है। जो प्रक्रियात्मक है वह उसके अभ्यास का तरीका है। इस प्रक्रिया में निष्पक्षता की इस गुणवत्ता पर मजबूत शब्द 'स्थापित' द्वारा बल दिया गया है जिसका अर्थ है 'दृढ़ता से स्थापित', न कि स्वेच्छा से या सनक से। यदि यह समुदाय की विधिक चेतना में निहित है तो यह 'स्थापित' प्रक्रिया बन जाती है। और 'कानून' इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि इसे आदर्श माना जाता है क्योंकि कानून साधन है और न्याय साध्य है।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय स्वतंत्रता का अपरिहार्य सार हैं। वास्तव में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इतिहास काफी हद तक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का इतिहास है और सुनवाई के अधिकार में मानव-अधिकार का घेरा शामिल है। भारत में गरीबी और अशिक्षा के कारण लोग अपने अधिकारों की रक्षा और बचाव करने में असमर्थ हैं; मौलिक अधिकारों के पालन को अच्छी राजनीति नहीं माना जाता और उनके उल्लंघन को बुरी राजनीति नहीं माना जाता।

संक्षेप में, अनुच्छेद 21 में 'प्रक्रिया' का अर्थ निष्पक्ष प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया नहीं। 'कानून' उचित कानून है, कोई अधिनियमित टुकड़ा नहीं।"

12. ...

13. ...

14. ...

15. **एक कैदी के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया का अन्य घटक, जिसे अदालती प्रक्रिया के माध्यम से अपनी मुक्ति की तलाश करनी है, अधिवक्ता की सेवाएं हैं। न्यायिक न्याय, प्रक्रियात्मक पेचीदगियों, विधिक प्रस्तुतियों और साक्ष्यों की आलोचनात्मक जांच के साथ, पेशेवर विशेषज्ञता पर निर्भर करता है; और कानून के तहत समान न्याय की विफलता उन कार्डों पर है जहां एक पक्ष के लिए ऐसा सहायक कौशल अनुपस्थित है।** हमारी न्यायपालिका, एंग्लो-अमेरिकन मॉडल द्वारा ढाली गई और हमारी न्यायिक प्रक्रिया, समान विधिक तकनीक द्वारा इंजीनियर की गई, कानून के तहत समान न्याय के पहियों को चलाने के लिए अधिवक्ता-शक्ति के सहयोग को मजबूर करती है। आवश्यकतामंदों को निःशुल्क विधिक सेवाएं अंग्रेजी आपराधिक न्याय प्रणाली का हिस्सा है। और येल के अमेरिकी न्यायविद् प्रोफेसर वेंस ने भी जो कहा वह भारत के लिए भी

सार्थक है, जब उन्होंने कहा,

> एक गरीब और अज्ञानी आदमी को इससे क्या लाभ कि वह कानून के समक्ष अपने प्रबल विरोधी के समान है, यदि उसे यह बताने वाला कोई नहीं है कि कानून क्या है? या कि न्यायालय अन्य सभी व्यक्तियों की तरह ही उसके लिए भी खुली हैं, जब उसके पास प्रवेश शुल्क का भुगतान करने का साधन नहीं है?"
>
> (बल दिया गया)

60. इसके बाद, यह न्यायालय ***अनोखीलाल बनाम मध्य प्रदेश सरकार*** में पारित निर्णय पर आगे बढ़ता है। जो वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में विचार करने के लिए बहुत जरूरी और उपयुक्त है। ***अनोखीलाल*** (सुप्रा.) में एक नाबालिग से बलात्कार और हत्या के मामले में दी गई मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर की गई थी। इस मामले में नौ वर्ष की पीड़िता अपने पड़ोसी के लिए बीड़ी लेने एक दुकान पर गई थी और फिर वापस नहीं लौटी. बाद में, वह 12 एआईआर 2020 एससी 232 एक खुले मैदान में मृत पायी गयी। यह देखा गया कि इस मामले में न्याय-मित्र के पास न तो मौलिक कागजात का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय था और न ही उन्हें अभियुक्त के साथ किसी भी संचार का लाभ मिला क्योंकि न्याय-मित्र को उसी दिन नियुक्त किया गया था जब आरोप तय किए जा रहे थे। उसके पास इस विषय पर सोचने का समय ही नहीं था। मुकदमा अगले चौदह दिनों के भीतर समाप्त हो गया और न्याय-मित्र के रूप में प्रदान की गई सहायता को माननीय उच्चतम न्यायालय ने वास्तविक और सार्थक नहीं माना। अन्य स्पष्ट खामियां भी देखी गईं, उनमें से एक यह थी कि सात दिनों की अवधि के भीतर 13 गवाहों की जांच की गई थी, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्तों का बयान अभियोजन पक्ष द्वारा पूरा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने से पहले दर्ज किया गया था। निष्पक्ष सुनवाई के आवश्यक घटक होने के नाते निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान के पहलू पर प्रचलित कानून और मिसालों पर ***अनोखीलाल*** (सुप्रा.) में चर्चा की गई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया था जो उनके द्वारा संदर्भित न्यायिक घोषणाओं से उभरे थे।

> "13. इसलिए, निम्नलिखित सिद्धांत यहां ऊपर उल्लिखित निर्णयों से उभरते हैं:
>
> क) वर्ष 1977 में संविधान में 42$^{वें}$ संशोधन द्वारा शामिल अनुच्छेद 39-क, यह सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता

है कि आर्थिक या अन्य विकलांगताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधिनियमन सहित लागू की गई वैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद 39-क के अधिदेश को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

ख) यह अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है कि निःशुल्क विधिक सेवाओं का अधिकार किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के लिए 'उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण' प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है और इसे अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकार में अंतर्निहित माना जाना चाहिए बेस्ट बेकरी केस13 में इस न्यायालय के निर्णय का उद्धरण (जैसा कि मोहम्मद हुसैन14 के निर्णय में उद्धृत किया गया है) इस बात पर बल देता है कि आपराधिक मुकदमे का उद्देश्य सत्य की खोज करना है और मुकदमा कोई तकनीकी पहलुओं पर लड़ाई नहीं है और इसे ऐसे तरीके से संचालित किया जाना चाहिए जिससे निर्दोषों की रक्षा हो सके और दोषियों को दंडित किया जा सके।

ग) संविधान में अनुच्छेद 39-क को शामिल करने से पहले ही, बशीरा15 में इस न्यायालय के निर्णय ने मामले को किसी भी संदेह से परे रखा और माना कि उस मामले में न्याय-मित्र को बचाव की तैयारी के लिए दिया गया समय पूरी तरह से अपर्याप्त था और वह मौत की सज़ा देने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को जीवन से वंचित होना पड़ा और यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन था।

घ) उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति सुब्बा राव, जे. द्वारा लिखित मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय से बशीरा[16] में उद्धृत भाग में स्पष्टता के साथ कहा गया है कि केवल नियम का औपचारिक अनुपालन जिसके तहत अधिवक्ता को बचाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाना था नियम में अंतर्निहित उद्देश्य को पूरा नहीं करना होगा। आगे कहा गया कि अवसर वास्तविक होना चाहिए जहां अधिवक्ता को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।

ङ) बशीरा17 के साथ-साथ अंबादास18 में, एक अधिवक्ता को न्याय-मित्र के रूप में नियुक्त करने के अगले ही दिन मामले में पर्याप्त प्रगति करना, इस न्यायालय द्वारा अधिवक्ता को 'पर्याप्त अवसर' के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।"

61. ***अनोखीलाल*** (सुप्रा.) में आगे देखा गया कि पूरा मुकदमा एक महीने से भी कम समय में समाप्त हो गया लेकिन जल्दबाजी में निपटान के कारण कई कमियाँ हुईं। बेंच ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"17. वी.के. शशिकला बनाम पुलिस अधीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व: (2012) 9 एससीसी 771 में इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार चेतावनी व्यक्त की गई थी:

> 23.4 जबकि मुकदमे को जल्द से जल्द निष्कर्ष पर लाने की चिंता को साझा किया जाना चाहिए, यह मौलिक है कि इस प्रक्रिया में कानून के किसी भी अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का त्याग नहीं किया जाता है या समझौता नहीं किया जाता है, जो कि न्यायिक मिसालों को उजागर करके कड़ी मेहनत से बनाया गया है। किसी भी परिस्थिति में, न्याय के उद्देश्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, हालांकि, निस्संदेह, यह बेहद वांछनीय है कि किसी भी मुकदमे का अंतिम परिणाम जल्द से जल्द संभव हो।
>
> 18. आपराधिक मामलों में त्वरित निपटान निस्संदेह आवश्यक है और यह स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी का हिस्सा होगा। हालाँकि, प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास निष्पक्षता के मूल तत्वों और अभियुक्त को अवसर की कीमत पर नहीं होने चाहिए, जिस पर न्याय का संपूर्ण आपराधिक प्रशासन आधारित है। **शीघ्र निपटान की चाह में, न्याय के उद्देश्य को कभी भी प्रभावित या बलिदान नहीं होने दिया जाना चाहिए, जो सर्वोपरि है, वह न्याय का उद्देश्य है और बुनियादी तत्वों को सुरक्षित रखना जो इसे एक मूल विचार और आदर्श के रूप में सुरक्षित रखते हैं, प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया की तेजी से ट्रैकिंग का परिणाम कभी भी न्याय के उद्देश्य को दफन करना नहीं चाहिए।"**
>
> (बल दिया गया)

62. अंततः, दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया और यह निर्देश दिया गया कि मुकदमा नए सिरे से विचार-विमर्श के साथ चलाया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***अनोखीलाल*** (सुप्रा.) में कुछ मानदंड निर्धारित किए ताकि उस मामले में हुई गड़बड़ियाँ और कमियाँ दोबारा न दोहराई जाएँ। ये मानदंड हैं:

> "22. अलग होने से पहले, हमें कुछ मानदंड तय करने होंगे ताकि वर्तमान मामले में हमने जो कमज़ोरियाँ देखी हैं, वे दोबारा न हों:
>
> i) ऐसे सभी मामलों में जहां आजीवन कारावास या मौत की सजा की संभावना है, विद्वान अधिवक्ता जिन्होंने न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का प्रैक्टिस किया है, उन्हें किसी अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्याय-मित्र या विधिक सेवाओं के माध्यम से नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।
>
> ii) मौत की सजा की पुष्टि से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाने वाले सभी मामलों में, न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पहले न्याय-मित्र के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाना चाहिए।
>
> iii) जब भी किसी विद्वान अधिवक्ता को न्याय-मित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो अधिवक्ता को मामले की तैयारी करने में सक्षम बनाने

> के लिए कुछ उचित समय प्रदान किया जा सकता है। इस संबंध में कोई कठोर नियम नहीं हो सकता। हालाँकि, सामान्यतः न्यूनतम सात दिनों का समय उचित और पर्याप्त माना जा सकता है।
>
> iv) किसी भी विद्वान अधिवक्ता, जिसे अभियुक्त की ओर से न्याय-मित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है, को आम तौर पर संबंधित अभियुक्त के साथ बैठकें और चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस तरह की बातचीत मददगार सिद्ध हो सकती है जैसा कि इम्तियाज़ रमज़ान खान[19] में देखा गया था।"

63. यदि इस मामले में मुकदमे की कार्यवाही के तरीके का अध्ययन किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त के अधिवक्ता को पर्याप्त और उचित समय नहीं मिला, जैसा कि ऊपर बिंदु (iii) में बताया गया है, बल्कि डीएलएसए नियुक्त अधिवक्ता को चालान के कागजात उसी दिन दिए गए जिस दिन उन्हें डीएलएसए द्वारा नियुक्त किया गया था और वास्तव में, उसी दिन आरोप तय किए गए थे। इस न्यायालय का मानना है कि अभियुक्त और उसके अधिवक्ता के बीच सही अर्थों में अधिवक्ता-ग्राहक संबंध स्थापित और विकसित नहीं हो सका है।

64. अभियुक्त से पूछताछ की जानी चाहिए कि क्या वह अपनी पसंद के अधिवक्ता को नियुक्त करने का इच्छुक है या क्या उसे विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता की आवश्यकता है जैसा कि ***अनोखीलाल*** (सुप्रा.) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अभिनिर्धारित किया गया है, हालांकि, वही था मौजूदा मामले में भी इसे अपनाया गया। गंभीर अपराधों सर्वोच्च द्वारा पारित निर्णय से जुड़े मामलों में आरोपी व्यक्तियों को एक वरिष्ठ अधिवक्ता/अग्रणी अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय का द्वारा दिए गए निर्णय अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता है न कि महज औपचारिकता बनकर रह जाने की। उक्त निर्णय पारित करने का उद्देश्य केवल औपचारिकता का पालन करना नहीं है बल्कि वास्तव में उसे विधिक सहायता प्रदान करना है ताकि उसके मौलिक अधिकार को पर्याप्त और उपयुक्त रूप से संरक्षित किया जा सके।

65. मुकदमे की प्रक्रियात्मक प्रगति में एक और वैधानिक गैर-अनुपालन और विसंगति यह थी कि वर्तमान मामले में लगाए गए आरोप सीआरपीसी की धारा 227 और 228 में निहित शर्तों के अनुरूप नहीं हैं जो आरोपमुक्त करने और आरोप तय करने की बात करते हैं। धारा 228 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी मामले में आरोप तय करने से

पहले मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के साथ-साथ आरोपी के साथ-साथ अभियोजन पक्ष की दलीलें भी सुनी जानी चाहिए। मौजूदा मामले में, चालान की एक प्रति आरोपी के अधिवक्ता को उसी दिन प्रदान की गई थी, जिस दिन उन्हें डीएलएसए द्वारा आरोपी-अपीलार्थी के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, अर्थात 28.09.2021 को। ट्रायल कोर्ट के दिनांक 28.09.2021 के आदेश-पत्र से यह प्रकट होता है कि संज्ञान के बिंदु के साथ-साथ आरोप तय करने के बिंदु पर भी 28.09.2021 को दलीलें तय की गईं। यह समझ से परे है कि जिस अधिवक्ता को 28.09.2021 को डीएलएसए द्वारा अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, वह वकालतनामा दायर करने और उसी दिन पर चालान पेपर की एक प्रति प्रदान करने के बाद आरोप तय करने के संबंध में संतोषजनक ढंग से दलीलें देने में कैसे सक्षम हो सकता है।

66. ***भारत संघ (यूओआई) बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल और अन्य***, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित ऐतिहासिक निर्णय में आरोप के विषय पर सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

> "10. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित अधिकारियों पर विचार करने पर, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:
>
> (1) कि संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायमूर्ति के पास यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्यों को छांटने और तौलने की निस्संदेह शक्ति है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं।
>
> (2) जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है, जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, तो न्यायालय आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से न्यायसंगत होगा।
>
> (3) प्रथम दृष्टया मामले को निर्धारित करने का परीक्षण स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम बनाना मुश्किल है। हालाँकि, यदि दो दृष्टिकोण समान रूप से संभव हैं और न्यायमूर्ति इस बात से संतुष्ट है कि उसके सामने प्रस्तुत किए गए साक्ष्य कुछ संदेह पैदा करते हैं, लेकिन आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह नहीं है, तो वह आरोपी को आरोपमुक्त करने के अपने अधिकार में पूरी तरह से होगा।
>
> (4) संहिता की धारा 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय नयायमूर्ति, जो वर्तमान संहिता के तहत एक वरिष्ठ और अनुभवी नयायमूर्ति है, केवल एक डाकघर या अभियोजन के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि उसे व्यापक संभावनाओं पर विचार करना

होगा। मामले का विवरण, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों का कुल प्रभाव, मामले में दिखाई देने वाली कोई बुनियादी कमज़ोरियाँ इत्यादि। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नयायमूर्ति को मामले के पक्ष और विपक्ष की गहन जाँच करनी चाहिए और साक्ष्यों को ऐसे तौलना चाहिए जैसे कि वह कोई सुनवाई कर रहा हो।

67. ***एच.जी. ग्रोवर बनाम राजस्थान सरकार*** नामक एक विस्तृत निर्णय को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2022 के तहत आदेश पारित किया गया था जिसमें आरोप तय करने की प्रक्रिया पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और आरोप तय करने से पहले जिन सभी पहलुओं पर विचार करने और ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उन्हें भी पूरी तरह से और व्यापक रूप से निपटाया गया है। उपर्युक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

> "16. आरोप तय करना न्यायमूर्ति द्वारा की गई एक निर्णायक कार्रवाई है क्योंकि किसी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने या उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से आरोपी को मुक्त करने के निर्णय के अधीन, दो परिणाम उत्पन्न होते हैं; या तो अभियोजन पक्ष (राज्य या शिकायतकर्ता) को बहस का मुद्दा मिलता है, अर्थात आरोपमुक्त करने के आदेश को चुनौती देने के लिए या आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि आरोपी के खिलाफ आरोपित धाराओं के तहत अपराध तय करने के लिए आवश्यक सामग्री या परिस्थितियों की जांच किए बिना भी आरोप तय किए जाते हैं, तो आरोपी को मुकदमे की कठोरता का सामना करना पड़ता है जो उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अंततः वह अपने ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों से बरी हो सकता है। न्यायमूर्ति की राय के लिए 'अनुमान लगाना' शब्द को ईजसडेम जेनेरिस पढ़ा जाना चाहिए कि एक आधार है; मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर राय बनाने का आधार कि एक व्यक्ति ने अपराध किया है और इस प्रकार, उस पर उस अपराध के तहत आरोप लगाया जाएगा। कुछ हद तक, यदि बचाव की दलील दी जाती है कि आपराधिक कार्यवाही किसी अन्य वैधानिक प्रावधान द्वारा वर्जित है, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है और एक अनंतिम राय बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि आरोप तय करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थायी राय बनाने के बिंदु पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या ऐसे तत्व और तथ्य हैं जो उस अपराध तय करने के लिए पर्याप्त हैं जिसके लिए आरोप तय किया जा रहा है। आरोपी है या नहीं।

68. चूंकि वर्तमान मामले में आरोप गंभीर प्रकृति के अपराध से संबंधित है, इसलिए चालान कागजात/अंतिम रिपोर्ट/आरोप प्राप्त करने के बाद आरोपी के साथ-साथ आरोपी के

अधिवक्ता को अपना बचाव तैयार करने के लिए उचित और पर्याप्त समय प्रदान किया जाना चाहिए। उस स्तर पर शीट और अन्य आवश्यक दस्तावेज, यदि कोई हो।

69. विधायिका की मंशा और संहिता की योजना से संकेत मिलता है कि आरोप तय करने के बाद, गवाहों की जांच के लिए ट्रायल जज द्वारा एक तारीख तय की जानी है। संदर्भ में आसानी के लिए सीआरपीसी की धारा 230 और 231 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> **230. अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख -** यदि अभियुक्त दलील देने से इनकार करता है, या दलील नहीं देता है, या मुकदमा चलाए जाने का दावा करता है या धारा 229 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाता है, तो न्यायमूर्ति गवाहों की परीक्षा के लिए एक तारीख तय करेगा, और अभियोजन पक्ष के आवेदन पर, कोई भी आदेश जारी कर सकता है। किसी गवाह को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज़ या अन्य चीज़ प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के कोई भी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।
>
> **231. अभियोजन के लिए साक्ष्य- (1)** इस प्रकार निर्धारित तिथि पर, न्यायमूर्ति ऐसे सभी साक्ष्य लेने के लिए आगे बढ़ेगा जो अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
> (2) न्यायमूर्ति, अपने विवेक से, किसी भी गवाह की जिरह को तब तक स्थगित करने की अनुमति दे सकता है जब तक कि किसी अन्य गवाह या गवाहों की जांच नहीं हो जाती है या किसी गवाह को आगे की जिरह के लिए वापस बुला सकता है।

70. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह पता चलता है कि मुकदमे की कार्यवाही में आरोप तय होने के बाद, और आरोपी ने स्वयं को दोषी नहीं माना है और उसके बाद सीआरपीसी की धारा 229 के तहत दोषी ठहराया गया है, तो गवाहों की जांच के लिए एक तारीख तय की जाती है। यह दर्शाता है कि तैयारी और प्रस्तुति के लिए अभियुक्तों के साथ-साथ अभियोजन पक्ष को अपने मामले को फिर से तैयार करने और किसी भी पूर्वाग्रह से छुटकारा पाने के लिए गवाहों की जांच शुरू करने से पहले एक राहत/विराम दिया गया है, वर्तमान मामले में देखा गया है लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। गवाहों से पूछताछ की तारीख तय करने का मतलब यह नहीं है कि आरोप शाम को तय किए जाएंगे और तीन-चार गवाहों से पूछताछ की तारीख अगली सुबह तय की जाएगी, जिससे आरोपी को बीच की रात में अपने अधिवक्ता से बातचीत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। प्रावधान में 'एक तारीख तय करें' वाक्यांश के उपयोग का इरादा इस तरह से नहीं लगाया जा सकता है अन्यथा विद्वान सत्र न्यायाधीश और अभियोजक को एक ही तारीख पर गवाहों की गवाही

दर्ज करने से कौन रोक रहा था।

71. यह सुनिश्चित करने में असमर्थता कि अभियुक्त के विधिक सहायता के अधिकार का सही अर्थों में प्रयोग किया गया था या अभियुक्त को बचाव का उचित अवसर दिया गया था, संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। विधिक अभ्यावेदन का अधिकार महत्वपूर्ण है और इसकी गारंटी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के साथ-साथ भारत के संविधान और यहां तक कि अन्य विधिक सहायता योजनाओं द्वारा दी गई है और माननीय उच्चतम न्यायालय की घोषणाओं की एक श्रृंखला द्वारा संरक्षित है। ऐसे कई अवसर आए हैं जब किसी अधिवक्ता की विधिक सेवा की अनुपस्थिति पुन: सुनवाई के आदेश का कारण बनी है या निचली अदालत द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय को रद्द कर दिया गया है और यह आदेश दिया गया है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई नया मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए; किसी अभियुक्त की निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार त्वरित सुनवाई के अधिकार से भिन्न है क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, यदि बाधित होता है, तो अभियुक्त की खुद का बचाव करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जबकि इसे त्वरित सुनवाई के अधिकार के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। .

72. ***बेस्ट बेकरी केस*** में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक मुकदमा सिर्फ एक बवंडर मामला नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें मुद्दे हैं अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता के संबंध में प्रश्न का उत्तर देने के लिए न्यायमूर्ति द्वारा जांच की जाती है और यह एक आपराधिक मामले में निष्पक्ष रूप से तभी किया जा सकता है जब कानून के सिद्धांतों का पालन किया जाता है और परीक्षण के दौरान उक्त सिद्धांतों का औपचारिक पालन करके न्याय की हत्या को विफल किया जाता है। ***बेस्ट बेकरी केस*** (सुप्रा.) के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

> "35. एक आपराधिक मुकदमा मामले में मुद्दों की न्यायिक जांच है और इसका उद्देश्य किसी तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के रूप में किसी मुद्दे पर निर्णय पर पहुंचना है जिससे तथ्यात्मक मुद्दे की खोज हो सके और ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो सकें वे तथ्य जिन पर अभियोजन पक्ष और अभियुक्त अपनी दलीलों से पहुंचे हैं; नियंत्रित करने वाला प्रश्न अभियुक्त का अपराध या निर्दोषता है। चूँकि उद्देश्य न्याय दिलाना और दोषियों को दोषी ठहराना और निर्दोषों की रक्षा करना है, इसलिए मुकदमा एक खोज होना चाहिए सच्चाई के लिए और तकनीकीताओं से अधिक नहीं, और ऐसे नियमों के तहत आयोजित किया जाना चाहिए जो निर्दोषों की रक्षा करेंगे,

> और दोषियों को दंडित करेंगे। आरोप का साक्ष्य जो उचित संदेह से परे होना चाहिए, साक्ष्यों की समग्रता के न्यायिक मूल्यांकन पर निर्भर होना चाहिए, मौखिक और परिस्थितिजन्य, और पृथक जांच से नहीं।
>
> 36. अभियुक्त या अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई देने में विफलता कानून की उचित प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों का भी उल्लंघन करती है। यह कानून की उचित प्रक्रिया की अवधारणा में अंतर्निहित है, कि निंदा केवल मुकदमे के बाद ही की जानी चाहिए जिसमें सुनवाई वास्तविक हो, न कि दिखावा या मात्र दिखावा और दिखावा। चूंकि निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रक्रिया को संरक्षित करने के लिए एक अवसर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अति जल्दबाजी में चरण-प्रबंधित, अनुरूप और पक्षपातपूर्ण परीक्षण द्वारा दूषित और उल्लंघन किया जा सकता है।
>
> 37. किसी आपराधिक अपराध के लिए निष्पक्ष सुनवाई में न केवल फ्रेम और कानून के रूपों का तकनीकी पालन शामिल है, बल्कि सच्चाई का पता लगाने और न्याय की हत्या को रोकने के लिए इसके सिद्धांतों को मान्यता और उचित रूप से लागू करना भी शामिल है।"

73. <u>उचित/पर्याप्त विधिक सहायता का अभाव:</u>

विद्वान ट्रायल कोर्ट की मूल फ़ाइल के अवलोकन से यह पता चलता है कि अभियुक्तों को प्रदान किए गए अधिवक्ता ने ट्रायल और अन्य अदालती कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयानों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया। ऐसे में यह कोर्ट एक प्रश्न से हैरान है जो सामने आया है कि अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए केस का आधार क्या था और वह अंतिम दलीलें कैसे तैयार कर पाया। यह इस न्यायालय को विश्वास दिलाता है कि विद्वान न्यायमूर्ति द्वारा यह उल्लेख करना कि उन्होंने निर्णय में अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत अंतिम दलीलें सुनी थीं, निश्चित रूप से एक खाली औपचारिकता थी। इस न्यायालय के लिए यह समझ से परे है कि अभियुक्त के अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही से संबंधित कोई कागज़ात के बिना न्यायालय में अपनी दलीलें कैसे दीं। आम बोलचाल की भाषा में, ऐसे मामले में जिसमें सजा की मात्रा मौत या आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, आरोपी की ओर से प्रस्तुत होने वाला एक अधिवक्ता मुकदमे में दर्ज गवाहों के बयानों के साथ-साथ अन्य आदेश-पत्रों और प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करता है। साक्ष्य में. इसके बाद, वह पहले दर्ज किए गए बयानों को देखता है जो उसे आरोप-पत्र के साथ प्रदान किए गए थे और अपने विधिक कौशल और ज्ञान के आधार पर एक रणनीति विकसित करता है और फिर उसी के आधार पर तर्क प्रस्तुत करता है। यदि कोई अधिवक्ता मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए

साक्ष्यों के एक भी कागज को स्कैन/परचे/अध्ययन किए बिना अपनी दलीलें पूरी करता है तो यह विधिक अभ्यास का मजाक है।

74. यह न्यायालय यह कहने में संकोच नहीं कर रहा है कि हालांकि ट्रायल कोर्ट ने निर्णय में कहा कि अभियुक्तों के अधिवक्ता की दलीलें सुनी गई थीं, लेकिन रिकॉर्ड के अवलोकन पर उभरती परिस्थितियों के प्रकाश में, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है लेकिन यह अनुपालन का मात्र एक नकली प्रदर्शन और एक दिखावा है। आपराधिक नियमों में यह प्रावधान है कि यदि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है तो न्यायिक कार्यवाही की प्रतियां उसे निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी, लेकिन पूरी फाइल में इसकी भनक तक नहीं लगती कि कभी अभियुक्त को कोई प्रति उपलब्ध करायी गयी हो। हालाँकि, आरोपी के अधिवक्ता को चालान कागजात की एक प्रति प्रदान की गई थी, तथापि, यह समझ में नहीं आता है कि आरोपी के अधिवक्ता को 28.09.2021 को चालान कागजात की एक प्रति प्राप्त हुई, न्यायालय के समय के दौरान पूरे चालान कागजात देखे गए और वह संज्ञान के बिंदु के साथ-साथ आरोप के बिंदु पर भी बहस करने में सक्षम थे। जिरह एक कौशल है और इसे केवल अच्छा अनुभव और कार्य में निपुणता रखने वाला अधिवक्ता ही कर सकता है और अभियुक्तों के लिए नियुक्त अधिवक्ता को नियुक्ति की अगली तारीख पर अपने मुवक्किल से मिलने का समय दिए बिना चार गवाहों से जिरह का कठिन कार्य करना पड़ता है।

75. यहां तक कि जहां अभियुक्त को वैध बचाव उपलब्ध होता, वह ऐसे बचाव का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है क्योंकि रिकॉर्ड से यह प्रतीत हो रहा है कि अभियुक्त को प्रदान की गई विधिक सहायता नाममात्र के लिए थी। हालाँकि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों में विसंगतियाँ थीं, लेकिन उन्हें इस तरह से सामने नहीं लाया गया जिससे अभियुक्तों के बचाव को मजबूत किया जा सके। इसी तरह इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आरोपी के शरीर पर दो चोटें कैसे पाई गईं.

76. <u>अटार्नी-ग्राहक विशेषाधिकार:</u>

कानून एक अधिवक्ता और उसके मुवक्किल के बीच आदान-प्रदान को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 में यह प्रावधान है कि ग्राहक और अधिवक्ता के बीच किसी भी पेशेवर संचार का आदान-प्रदान किया जाता है, जिसमें अधिवक्ता द्वारा ग्राहक के साथ साझा की गई कोई भी सलाह, ग्राहक द्वारा अधिवक्ता

को बताई गई कोई भी जानकारी या किसी दस्तावेज़ की सामग्री या स्थिति शामिल है जो इसके दौरान और उसके रोजगार के उद्देश्य के बारे में अधिवक्ता को दी, ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है। धारा 126 को यहां उपयोगी संदर्भ के लिए पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> **126. व्यावसायिक संचार** - किसी भी बैरिस्टर, अधिवक्ता को किसी भी समय अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसके ग्राहक की स्पष्ट सहमति न हो, इस दौरान और बैरिस्टर, अधिवक्ता के रूप में उसके रोजगार के उद्देश्य से उससे किए गए किसी भी संचार का खुलासा करने के लिए, अधिवक्ता या अधिवक्ता, अपने मुवक्किल द्वारा या उसकी ओर से, या किसी दस्तावेज़ की सामग्री या स्थिति को बताने के लिए जिसके साथ इस दौरान में और अपने पेशेवर रोजगार के उद्देश्य से परिचित हो गया है या उसके द्वारा दी गई किसी भी सलाह का खुलासा करने के लिए इस दौरान में और ऐसे रोजगार के प्रयोजन के लिए ग्राहक: बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी प्रकटीकरण से रक्षा नहीं करेगा -
>
> (1) किसी अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया ऐसा कोई संचार;
>
> (2) किसी बैरिस्टर, अधिवक्ता, अधिवक्ता या अधिवक्ता द्वारा अपने रोजगार के दौरान देखा गया कोई भी तथ्य, जो दर्शाता है कि उसके रोजगार के शुरू होने के बाद से कोई अपराध या धोखाधड़ी हुई है।
>
> यह मायने नहीं रखता कि ऐसे बैरिस्टर, अधिवक्ता, अधिवक्ता या अधिवक्ता का ध्यान उसके मुवक्किल द्वारा या उसकी ओर से ऐसे तथ्य की ओर गया था या नहीं।
>
> *स्पष्टीकरण* इस खंड में बताई गई बाध्यता रोजगार समाप्त होने के बाद भी जारी रहती है।

77. साक्ष्य अधिनियम के उपरोक्त उद्घृत प्रावधान को संदर्भित करने का उद्देश्य भारतीय साक्ष्य कानून के प्रचलित आपराधिक क़ानून से बाहर निकलना है कि एक संचार जिसमें ग्राहक द्वारा नियोजित अधिवक्ता के बीच महत्वपूर्ण जानकारी के साथ-साथ सलाह का आदान-प्रदान शामिल है जिसकी वैधानिक रूप से परिकल्पना की गई है और इस प्रकार, इस पहलू पर अधिक बल दिया गया है कि वर्तमान मामले में आरोपी को पर्याप्त तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम होने के लिए अपने अधिवक्ता से बातचीत और परामर्श करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

78. अधिवक्ता और वादी के बीच बातचीत जरूरी है क्योंकि प्री-ट्रायल चरण में किसी भी कानून में यह धारणा नहीं है कि आरोप-पत्र में बताई गई कहानी सच है और सतह के नीचे कुछ भी नहीं है। और यह जानने के लिए अधिवक्ता और वादी के बीच बातचीत

जरूरी है। प्राचीन काल से एक प्रथा/सम्मेलन/संस्कृति रही है कि एक अधिवक्ता और एक वादी के बीच कुछ संचार होना चाहिए और इस प्रकार, एक अधिवक्ता के गैर-प्रकटीकरण का विशेषाधिकार आपराधिक कानून में निर्धारित है।

79. अंत में, एक और पहलू जिसने इस न्यायालय को प्रभावित किया है, वह यह है कि आम तौर पर, एक महानगरीय शहर में पोस्को अधिनियम के मामलों से संबंधित न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले एक ट्रायल जज के पास उसकी दैनिक वाद-सूची और इस प्रकार सूचीबद्ध मामलों में सिर्फ एक भी मामला सूचीबद्ध नहीं होगा और ऐसा सूचीबद्ध मामला परीक्षण के विभिन्न चरणों में होगा। उदाहरण के लिए, मामले संज्ञान लेने, आरोप तय करने, गवाहों की जांच के लिए बुलाने, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य दर्ज करने, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी से स्पष्टीकरण मांगने, बचाव साक्ष्य की रिकॉर्डिंग/जोड़ने, से लेकर अंतिम दलीलों की सुनवाई, दोषसिद्धि का निर्णय पारित करने और सजा का आदेश देने के चरणों तक संबंधित हो सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विभिन्न चरणों में आगे बढ़ने वाले मामलों के अलावा, जमानत आवेदनों के साथ-साथ अन्य विविध और छिट-पुट आवेदन भी निपटाए जाने हैं। इस न्यायालय को अवगत कराया गया है कि विशेष न्यायमूर्ति, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, क्रमांक 03, जयपुर महानगर-I के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रतिदिन औसतन 10-15 मामले सूचीबद्ध होते हैं। इस विशेष न्यायालय में 500 से अधिक मामले लंबित हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय यह समझने में विफल रहता है कि इस विशेष, वर्तमान मामले पर कैसे और क्यों इतनी जल्दबाजी में और इस तरह से कार्यवाही की गई जैसे उस सप्ताह की केवल और केवल वर्तमान आरोपी-अपीलार्थी का मामला ही बोर्ड में सूचीबद्ध किया गया हो।

80. यद्यपि ट्रायल जज ने दुर्भावना से या किसी गुप्त उद्देश्य से कार्य नहीं किया होगा, तथापि, यह न्यायालय सावधानी व्यक्त करने के लिए बाध्य महसूस करता है क्योंकि तत्काल मामले का पीठासीन अधिकारी भविष्य में अन्य मामलों में भी मीडिया और जनता से मिलने वाली प्रशंसा को देखते हुए इसी तरह कार्य कर सकता है जिससे न्याय के हित की अनदेखी हो सकती है।

81. न्याय केवल मामले के एक पक्ष को प्रदान करने का इरादा नहीं है। न्याय तभी हुआ माना

जाएगा जब यह प्रभावित सभी पक्षों को प्रदान किया जाएगा और साथ ही व्यापक सामाजिक हित में भी किया जाएगा। पूर्ण न्याय तब होता है जब वह समाज सहित न्याय के सभी पक्षों तक पहुंचता है।

82. यहां ऊपर की गई टिप्पणियों का उद्देश्य और इच्छित प्रभाव यह नहीं है कि ट्रायल जज को मामले के निपटारे में अधिक समय लेना चाहिए, बल्कि ट्रायल को तेजी से संचालित करते समय उन्हें सावधान रहना होगा ताकि पक्षकारों के अधिकारों पर असर न पड़े। केवल तत्परता ही विवेक के गुण का आवश्यक हिस्सा नहीं बनती।

83. यहां ऊपर की गई चर्चा के परिणामस्वरूप, निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि को बरकरार रखने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है। यह न्यायालय विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्ष और जिस तरीके से मुकदमा समाप्त हुआ, उससे सहमत नहीं है और इसलिए, उसे खारिज कर देती है। अपील पिछले पैराग्राफ में चर्चा किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार अनुमति दिए जाने योग्य है।

84. इस निर्णय के परिणाम की ओर लौटते हुए, यह न्यायालय आरोप तय करने के बिंदु से पहले विद्वान परीक्षण न्यायाधीश द्वारा नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश देना उचित समझता है।

85. विद्वान ट्रायल जज को निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुए नए सिरे से विचार करते हुए ट्रायल चलाना होगा:

i) ट्रायल जज सीआरपीसी की धारा 226-228 के तहत निहित प्रावधानों का पालन करेंगे।

ii) ट्रायल जज गवाहों को नए समन जारी करेंगे।

iii) पीड़िता को बाल अनुकूल माहौल में अपना बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय में बुलाया जाएगा जो उसके लिए निडर और स्वतंत्र रूप से न्यायालय के सामने गवाही देने के लिए पर्याप्त अनुकूल हो।

iv) पीड़िता को सहज महसूस कराने के लिए सुनवाई के दौरान एक ऐसे व्यक्ति को उसके साथ जाने की अनुमति दी जाएगी जिस पर पीड़िता को अवलंब है।

v) यदि विद्वान न्यायमूर्ति को यह महसूस होता है कि बच्चा पर्याप्त रूप से सहज नहीं है और बाल परामर्शदाता की सहायता की आवश्यकता है, तो बाल देखभाल गृह, अन्य

संस्थानों जो बाल देखभाल में विशेषज्ञ हैं, सरकारी एजेंसी या सरकारी एन.जी.ओ. से ट्रायल के दौरान बच्चे का आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए परामर्शदाता को बुलाया जा सकता है।

vi) पीड़िता को सीधे आरोपी के सामने नहीं लाया जाएगा। आरोपी को पर्दा करके अलग सेक्शन में खड़ा किया जाएगा।

vii) जहां तक संभव हो, आरोपी को पीड़िता के सामने शारीरिक रूप से दिखाया नहीं जाना चाहिए। औपचारिक पहचान के उद्देश्य से उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या डिजिटल फोटोग्राफ का उपयोग करके पीड़ित को दिखाया जा सकता है जिसे न्यायालय की स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है, हालांकि, यदि आरोपी को पीड़ित के सामने शारीरिक रूप से प्रदर्शित होना है, तो ऐसा ही मुख्य परीक्षा के अंत में किया जाएगा।

viii) पोस्को अधिनियम के मामलों के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रिया/दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

ix) अनावश्यक प्रश्न पूछकर गवाहों को परेशान नहीं किया जा सकता।

x) पीड़ित से ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता जो स्वयं में या एक निश्चित तरीके से पूछे जाने पर कष्टप्रद, निंदनीय और अप्रासंगिक हो जाए।

xi) किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xii) ट्रायल जज मामले का निर्णय गुणागुण और निष्कर्ष के आधार पर कर सकता है। दोष सिद्ध हो गया है और अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है, तो सजा की सुनवाई कानून की सीमा के भीतर की जानी चाहिए जैसा कि निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

xiii) ट्रायल जज इस निर्णय में की गई किसी भी टिप्पणी से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे।

86. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। सत्र वाद संख्या 28/2021 में विद्वान विशेष न्यायमूर्ति, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, संख्या 03, जयपुर महानगर-I द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और सजा का आदेश दिनांक 05.10.2021 को रद्द कर दिया गया है और जैसा कि पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई है,

मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया गया है।

87. कहने की आवश्यकता नहीं है, यहां ऊपर की गई कोई भी टिप्पणी ट्रायल जज को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी, जिससे किसी भी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इस न्यायालय ने खुद को मामले की योग्यताओं से निपटने से रोक दिया है और विद्वान ट्रायल जज को इसके निर्णय पैराग्राफ संख्या 85 में सूचीबद्ध दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए आरोप तय करने के चरण से नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

88. अलग होने से पहले, यह न्यायालय अपील की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय की सहायता करने के लिए अधिवक्ता अनुभा सिंह के प्रयासों की सराहना करता है। उनके समर्पण की उचित सराहना की जाती है।

(फरजंद अली), न्यायमूर्ति

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।